the Government. There is no change, except their saying that they would go ahead with the elections and so on. It seems, this is the only strategy of the Government. What is the basic issue, Madam?

I would humbly request. There is a strategy which could be worked in these circumstances. I have been mentioning a ten-point strategy. Ever since I was sent there as Governor for the second time, I have been saying that we should recognise the ground realities and work out a comprehensive strategy. But this, Madam, is not happening, with the result that this type of tragic incidents are being repeated.

Therefore, I would once again request the Government to take a fresh look at the situation and not confine their policy only to a, sort of, tape-recorded message, i.e. elections. We will have to take a very serious view of the situation in view of such things happening where army personnel are being kidnapped, where all types of people are being taken hostage, where so many killings are taking place. This is happening even in 1995. This is what I wanted to bring to the notice of the Government, through you. Thank you very much, Madam.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (BIHAR): Madam, I would take just one minute on this. Unfortunately, every day, this issue is coming up before the House in one shape or the other. This is very tragic. Unfortunately, we find a statute-like and a stoic silence on the part of the Government.

I have been talking about it for the past one week-about the bomb blasts in Jammu and other incidents there. I have pointed out again and again that there is a very consistent and sorted-out policy on the part of Pakistan to create such incidents. Last night, I heard, at length, the President of Pakistan talking to his journalists. One message came through very clearly through every source. That message is: Pakistan is bent upon doing the worst now. The tragedy is different. The tragedy is not what Pakistan does. The tragedy is the stoic silence on our part. People from all political parties, including the Congress, and all the Ministers who went there, have said that a change in the administration is needed. Silence. Ministers are sent. Ministers come back and report. Silence. I want to know. Is it or is it not a fact - I am not leaking out any secret - that even the Ministers, even those who were close to the Prime Minister who had been sent, have come back with the conclusion that a great deal of change was needed at the level of the Governor and at other levels of the administration as well? I do not know what we are waiting for. We are worried.

(*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): You will have the opportunity. We are going to have a discussion tomorrow.

SHRI JAGESH DESAI: Tomorrow we are discussing it.

SHRI S.B. CHAVAN: We are going to have a discussion on this issue tomorrow.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Discussion is a different thing.

(*Interruptions*)

Madam, yesterday, we co-operated. I am not sorry for that. Today a situation has come. Tomorrow we will be adjourning. And the whole thing will go on merrily. Kidnapping of seven officers is not a small thing. It is not something about which the Home Minister can afford to tell us, "I will let you know tomorrow." He should have come here to make a *suo-motu* statement in the morning and tell the nation what is happening and what he is going to do. Thank you.

SHRI SANATAN BESI (ORISSA): Madam, only one sentence.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Please sit down. Yes, Mr. Jagdesh Desai. Not on this?

SHRI JAGESH DESAI: On Rajiv Gandhi's death.

SHRI SANATAN BISI: Madam, I wanted to tell you about this thing because in the newspapers and over the radio the information is coming that the four foreign hostages are safe. We are reading that in the newspapers. The Home Minister should come forward with a statement as to what Pakistan is doing and what the Americans are doing.

RE. ALLEGED PUNISHMENT TO HINDI-SPEAKING STUDENTS AND TEACHERS IN A PUBLIC SCHOOL AT SHILLONG

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीया

उपसभाध्यक्ष महोदया, कहते है कि हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं और यह कहा जाता है कि भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है। यह विचित्र बात है कि आज के भारतवर्ष में हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं का कोई सम्मान नहीं। आज का भारतवर्ष जिस तबके के द्वारा संचालित होता है उस तबके के मुट्ठी भर बड़े करोड़पतियों या बड़े राजनेताओं या बड़े अधिकारियों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते है...(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: आज आप केन्द्रीय कक्ष में थे या नहीं?

श्री कृष्णलाल शर्मा: वहां सब भाषण अंग्रेजी में था।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: वहां उन बच्चों को भूले से भारतीय भाषा न आ जाए, इसकी व्यवस्था की जाती है। मां के दूध के साथ जो भाषा अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए, उसमें विद्यालयों में शिक्षा नहीं दी जाती। वह पब्लिक स्कूल हैं, वह बड़े स्कूल हैं और वह सरकार के द्वारा स्थापित स्कूल हैं। मैं जिस स्कूल की चर्चा कर रहा हूं वह स्कूल भारत के रक्षा विभाग के अधीन आसाम राईफल्स के द्वारा स्थापित पब्लिक स्कूल हैं। उस पब्लिक स्कूल में एक नियमावली है। उस नियमावली के पृष्ठ -91 पर यह नियम है कि विद्यालय के अंदर किसी भारतीय भाषा में विद्यार्थी बात नहीं कर सकते। .....(व्यवधान) मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच करवाएं। उस विद्यालय की नियमावली से छपा हुआ है कि विद्यालय के भीतर कोई विद्यार्थी किसी भारतीय भाषा में बात नहीं कर सकता। अब चूंकि वह केन्द्रीय विद्यालय है और इसलिए आंसू पोंछने के लिए वहां हिन्दी की कक्षाएं हैं। हिन्दी की कक्षाओं में हिन्दी पढ़ाई जाए, हिन्दी में बोला जाए, यह ठीक है। लेकिन हिन्दी की कक्षा के बाद कोई अगर हिन्दी में बात करता है तो उसको एक हजार बार, दो बार नहीं, सौ-दो सौ बार नहीं, एक हजार बार इस बच्चे को लिखना पड़ता है "I will not talk in Hindi I will talk in English."

यह भारतवर्ष है। मैं हिन्दी की बात नहीं कहता, मैं किसी भी भारतीय भाषा की बात कहता हूं। बंगाल में ऐसे स्कूल हैं जिसमें बंगला नहीं बोली जाती, अंग्रेजी में बोलना होता है। तमिलनाडु में ऐसे स्कूल हैं जिसमें तमिल नहीं बोली जाती। वे बड़े लोगों के स्कूल हैं, वह बड़े आदमियों के स्कूल है। कल जो भारत के भविष्य निर्माता होंगे वे बच्चे वहां पढ़ते हैं। मुझको रघुवीर सहाय की एक कविता याद आती है।

''पांच दशक बीत चले भरमे उपदेश में,
दो-दो पूरी पीढ़ियां जुन्मी, पली, पुसी क्लेश में,
बेबगानी हो गई अपने ही देश में।''

दो तरफ से बेगानापन-एक गरीबी के कारण और एक अमीरी के कारण। अमीरी के कारण जो बेगानापन आता है वह और भी खराब है। अपने ही बच्चे अपनी मातृभाषा नहीं जानते। मातृभाषा बोलने के अपराध पर उनको दंड मिलता है और उस स्कूल की चलाता है भारत सरकार का रक्षा विभाग। यह बहुत ही शर्म की बात है। मैं अभी विदेश में गया था। मुझसे हाइडेलवर्ग विश्व विद्यालय की हिन्दी अध्यापिका डा॰ मोनिका ने कहा था कि मैं 70 जर्मन लड़कों को हिन्दी सिखाकर अपराध कर रही हूं, क्योंकि मैं मानती हूं कि उनका कोई भविष्य नहीं है।

क्योकि मैं मानती हूं कि उनका कोई भविष्य नहीं है। मैं जब दिल्ली आती हूं तो मुझ से अंग्रेजी में बात की जाती है। और यह बात भी है कि हमारे विद्यालयों में भारतीय भाषा बोलना जुर्म हो सकता है, उसके लिए विद्यार्थी दंडित हो सकते हैं और अगर हिन्दी अध्यापक उसका विरोध करता है तो उस हिन्दी अध्यापक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं आप सब के माध्यम से यह गंभीर प्रश्न सरकार के विचारार्थ उठाना चाहता हूं। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए और अगर वह छपा हुआ नियम हो तो उस नियम को खारिज किया जाए। वहां पर अध्यापकों को निर्देश दिया जाए कि हिन्दी में या मातृभाषा में बोलना अपराध नहीं हैं मुझे और दुख है कि मेघालय के हमारे राज्यपाल उसके संरक्षक हैं, उस विद्यालय के। राज्यपाल के संरक्षण में यह नियमावली, राज्यपाल के संरक्षण में यह विधान और इस देश का नाम भारतवर्ष है जिसका बड़ा भारी गौरवपूर्ण अतीत रहा है, जिसकी भाषाएं दुनियां की किसी भाषा से भी मुकाबला कर सकती हैं, वहां भारतीय भाषाएं बोलना अपराध हो, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे सांसद मित्र इस बात का प्रतिवाद करें और इस बात की छानबीन हो, जांच-पड़ताल हो और उस नियम को अवश्य खारिज किया जाए जिसमें यह लिखा गया है कि भारतीय भाषाओं में कोई बात नहीं कर सकता है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: महोदया, मैं अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री एस. बी. चव्हाण: इसकी गवर्नमेंट की तरफ से जांच की जाएगी।

श्री शंकर दयाल सिंह: मै धन्यवाद दे रहा हूं उपसभाध्यक्ष महोदया जो गृह मंत्री जी ने कहा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी ने तो बयान दे ही दिया है।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): मै चाहता हूं कि जो शास्त्री जी ने मामला उठाया है गंभीरता के साथ कि वहां के जो हिंदी शिक्षक हैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, उनको केवल इस बात के लिए निकाल दिया गया उस स्कूल से कि वे अपने बच्चों को जो हिन्दी पढ़ते हैं, उनको यह कहते थे कि तुमको हिंदी का व्यवहार करना चाहिए। जब कि सरकारी स्कूल है, सरकारी रोज़गार समाचार समाचार में विज्ञापन जो निकला, उसके अनुसार 16 अप्रैल, 1954 को उनकी नियुक्ति हुई। उनके प्रति कोई दूसरा अपराध नहीं है। केवल उनका अपराध यह है कि जिस विषय के वे प्राध्यापक हैं या अध्यापक हैं, उस विषय को वे पढ़ा रहे हैं और जिन लड़कों को वे वह विषय पढ़ा रहे हैं, उसमें तुम हमसे बातचीत करो, वे यह कहते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से यह मांग करता हूं कि जांच का कार्य तो आप अवश्य करें लेकिन साथ-साथ ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी को हटाया गया, इसके लिए उनको सरकार को तुरंत बहाल करना चाहिए।

अंतिम बात माननीया मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा षड़यंत्र चल रहा है भारतीय भाषाओं के खिलाफ। कोई हमारी भाषा चाहे वह असमी हो, मणिपुरी हो या दूसरी भाषाएं हैं जो विकसित नहीं हो रही हैं, वहां आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी स्कूलों, अंग्रेज़ी पढ़ाई, रोमन लिपि का प्रचार-प्रसार हो, इसके लिए करोड़ों, अरबों रुपए कहां से खर्च किए जा रहे है, किसी को पता नहीं चल रहा है। वहां अभी भी पचासों ऐसी छोटी-मोटी बोलियां हैं जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है और जब तक किसी बोली के पास अपनी लिपि नहीं हो, भाषा का रूप वह ग्रहण नहीं कर सकती है। वहां से यह मांग आई थी बहुत दिन पहले कि देवनागरी लिपि का हम व्यवहार करना चाहते हैं इनके लिए। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय इसके लिए भी जांच कराएं, प्रयास कराएं और निश्चित रूप से इसे गंभीरता से सरकार ले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव: महोदया, एक मिनट मैं ..... **(व्यवधान).....**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): महोदया, इस ईश्यू के साथ हम अपने आपको जोड़ना चाहते हैं और उस अध्यापक को तुरंत वहां पर लगाया जाए, वापस भेजा जाए जिन्हें नौकरी से निकाला गया है, यह कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम, श्री शंकर दयाल सिंह जी ने और श्री विष्णु कान्त शास्त्री जी ने जिस विषय की ओर सरकार का और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और इसका पूरा समर्थन करता हूं। गृह मंत्री जी ने कहा कि जांच कराई जाएगी, मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि दो आश्वासन और दीजिए कि जांच कराई जाएगी, बात तो सही है लेकिन अगर जांच में से तथ्य सही पाए गए तो उस अध्यापक को तुरंत रीईस्टेट किया जाएगा और जिसने उन बच्चों को दंडित किया है हिन्दी बोलने के लिए, उसको भी दिया जाएगा, मैं इस तरह का भी गृह मंत्री जी से आश्वासन चाहता था और शास्त्री जी की और श्री शंकर दयाल सिंह जी की बातों का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): मैडम, मैं भी विष्णु कान्त शास्त्री जी के साथ और शंकर सिंह जी के साथ जैसे ईश दत्त यादव जी ने कहा है, भारत की जो आज़ादी की भाषा है, जिससे देश आज़ाद हुआ है, वह हिंदी भाषा है जो कि लिंक्ड भाषा थी। भारत की कितनी भाषाएं हैं ?

चाहे वह पंजाबी है, चाहे वह कन्नड़ है, चाहे वह हिन्दी है और चाहे वह कोई और भाषा है इनकी जो एक लिंक भाषा है वह हिन्दी है। जैसा विष्णु कान्त शास्त्री जी ने बताया कि बच्चों को यह कहा जा रहा है कि वे हिन्दी नहीं बोल सकते तो यह हमारे पूरे देश के लिए एक शर्मनाक घटना है। मैं यह चाहता हूं कि जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने सदन को विश्वास दिलाया कि इसकी इंक्वायरी करायेंगे तो इंक्वारी तो करानी ही चाहिए और उसके बाद इसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए जिससे कभी भी ऐसा न लगे कि अपने देश की भाषा को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। इतना ही मैं कहता हूं।

RE. SLOW PROGRESS IN THE PROBE INTO THE ASSASSIANTION OF SHRI RAJIV GANHDI

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदया, श्री राजीव गांधी जी की हत्या की साजिश की जांच के लिए जैन कमीशन का गठन 23 जून, 1991 को हुआ था जिसे इस सदन में सारी राजनीतिक पार्टियों के हमारे साथियों ने राजनीति से ऊपर उठकर इसका समर्थन किया था। उस जैन कमीशन का सातवीं बार एक्सटेंशन हुआ है और उसकी अवधि भी 31 अगस्त, 1995 है जो बहुत नजदीक है लेकिन अभी तक जैन कमीशन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। बल्कि इसके विपरीत कमीशन के चेयरमैन की बराबर यदाकदा यह टिप्पणी आती रही कि